

गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD, SURAT, LUCKNOW

वर्ष : 16
अंक : 194
दि. 15.11.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
AHMEDABAD EDITION

भगवंत मान के पाकिस्तान दौरे पर सियासी टकराव, केंद्र ने स्पष्ट की नीति



नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे को लेकर राजनीतिक विवाद गहराने लगा है। लाहौर में 27 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हालांकि, भारत और पाकिस्तान के मौजूदा संबंधों तथा पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से अपनाई गई नीति के मद्देनजर इस यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विदेश जाने वाले राजनीतिक पदाधिकारियों को मंजूरी देने का फैसला भारत की स्थापित राष्ट्रीय नीति के अनुरूप किया जाता है। मंत्रालय के इस रुख के बाद मुख्यमंत्री के पाकिस्तान दौरे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।

भगवंत मान ने 23 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा में इस निमंत्रण की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के दोनों पंजाब की जड़ें और संस्कृति एक जैसी हैं। इसी साझा सांस्कृतिक विरासत के आधार पर उन्होंने सम्मेलन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि यदि उन्हें पाकिस्तान जाने का अवसर मिलता है तो वे ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहेंगे। उनके इस बयान के बाद से ही प्रस्तावित यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मांग भी उठाई थी। उनका कहना था कि यदि केंद्र सरकार अनुमति देती है तो पंजाब विधानसभा के सभी दलों के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ पाकिस्तान जा सकता है। उन्होंने पूर्व में फ्रांस और जापान जैसे देशों की यात्रा के लिए अनुमति नहीं मिलने का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया था कि जब इन देशों में जाने की मंजूरी नहीं मिलती तो पाकिस्तान जाने की अनुमति कैसे मिलेगी। उनके इस बयान को केंद्र और राज्य सरकार के बीच विदेश यात्राओं की मंजूरी को लेकर जारी खींचतान के संदर्भ में देखा जा रहा है।

विदेश मंत्रालय ने 13 नवंबर को अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की एक स्थापित राष्ट्रीय नीति है और सभी से उसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने बताया कि विदेश यात्रा पर जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों को राजनीतिक मंजूरी देने से पहले मंत्रालय देश की समग्र नीति के अनुरूप मामले का आकलन करता है। प्रवक्ता ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति का भी उल्लेख किया। उनके बयान से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर निर्णय केवल सम्मेलन के निमंत्रण के आधार पर नहीं होगा, बल्कि भारत के मौजूदा कूटनीतिक रुख को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

इस बीच पाकिस्तान की ओर से भी भगवंत मान की संभावित यात्रा को लेकर बयान दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने 7 नवंबर को कहा था कि यदि मुख्यमंत्री पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनके वीजा आवेदन पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान की ओर से वीजा पर विचार करना और भारत सरकार से यात्रा की अनुमति मिलना दो अलग-अलग विषय हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने भी भगवंत मान, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां और विधायकों को सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिए जाने की पुष्टि की थी।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा ने सुरक्षा और आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। पंजाब भाजपा के मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता विनीत जोशी ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण पंजाब लंबे समय तक कठिन दौर से गुजरा है। उन्होंने सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों की कुर्बानियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री से पाकिस्तान का निमंत्रण स्वीकार करने से पहले पुनर्विचार करने की अपील की। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस निमंत्रण को ठुकरा देना चाहिए।

कांग्रेस ने भी प्रस्तावित यात्रा का विरोध किया है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के पीछे पाकिस्तान की भूमिका रही है। उन्होंने दावा किया कि सीमा पार से हथियार भेजे जाते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को वहां संरक्षण मिलता है। बेरी ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तानी टीम के पंजाब आने से इनकार करने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से भी पाकिस्तान का निमंत्रण अस्वीकार करने की मांग की।

इस तरह भगवंत मान के प्रस्तावित दौरे को लेकर मामला अब केवल सांस्कृतिक सम्मेलन में भागीदारी तक सीमित नहीं रह गया है। एक ओर मुख्यमंत्री साझा पंजाबी विरासत और धार्मिक स्थलों के दर्शन की इच्छा जता चुके हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों का हवाला देकर यात्रा का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के बयान के बाद अब सबकी निगाहें पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री के अगले कदम पर टिकी हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि भगवंत मान निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं और केंद्र सरकार उन्हें राजनीतिक मंजूरी देगी अथवा नहीं।

आखिरी ओवर में भारत का कमाल, पाकिस्तान को हराकर बना एशिया चैंपियन



अल अमेरात (ओमान)। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने असाधारण जज्बे, धैर्य और संघर्ष का परिचय देते हुए पाकिस्तान को रोमांचक फाइनल में एक विकेट से हराकर 2026 एसीसी पुरुष अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में जीत के लिए भारत के सामने 338 रन का विशाल लक्ष्य था। भारतीय टीम ने आखिरी ओवर तक चले उतार-चढ़ाव भरे संघर्ष में नौ विकेट खोकर 339 रन बनाए और खिताब पर कब्जा जमा लिया। जब लगातार विकेट गिरने से भारत की उम्मीदें कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थीं, तब मोहित उल्वा ने आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल दिया। चिगुरुपति वेंकट ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। दोनों की संयमित और साहसिक बल्लेबाजी ने भारत को ऐसी जीत दिलाई, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट पर 337 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की और बड़े शॉट खेलकर रन गति को बनाए रखा। उस्मान खान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 111 गेंदों पर 107 रन बनाए। उनकी पारी में धैर्य और आक्रामकता का अच्छा तालमेल देखने को मिला। उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सामना करते हुए शतक पूरा किया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उस्मान खान को अब्दुल कादिर का बेहतरीन साथ मिला। कादिर ने महज 54 गेंदों पर 80 रन की तेजतर्रार पारी खेली। उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाकर भारतीय गेंदबाजों को दबाव में रखा। कप्तान फरहान यूसुफ ने भी 63 रन बनाकर पाकिस्तान के बड़े स्कोर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन तीनों बल्लेबाजों की पारियों के दम पर पाकिस्तान ने भारत के सामने 338 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। भारतीय गेंदबाजों के लिए इस स्कोर को रोकना आसान नहीं रहा, लेकिन काव्या पटेल ने चार विकेट लेकर पाकिस्तान की रन गति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। चिगुरुपति वेंकट ने भी तीन विकेट हासिल कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

338 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआत से ही बड़े स्कोर के दबाव का सामना करना पड़ा। फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में हर विकेट की कीमत बढ़ गई थी। भारतीय बल्लेबाजों ने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए रन गति बनाए रखने की कोशिश की। कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने जिम्मेदारी संभाली और 80 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी की और टीम की उम्मीदों को मजबूती दी। उनके साथ आर्यवीर सहवाग ने भी 58 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों की पारियों ने भारत को लक्ष्य के करीब पहुंचाने की राह तैयार की।

इसके बाद मनल चौहान ने तेजी से रन बनाकर मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। उन्होंने केवल 32 गेंदों पर 47 रन की आक्रामक पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी से भारतीय खेमे में जीत की उम्मीदें और मजबूत हुईं। हालांकि, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए लगातार विकेट हासिल किए। एक समय ऐसा लगा कि भारत मजबूत स्थिति से फिसलकर मुश्किल में पहुंच गया है। विकेट गिरने के कारण लक्ष्य और करीब आने के बावजूद भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता चला गया। पाकिस्तान को भी विश्वास होने लगा कि वह मुकाबले में वापसी कर सकता है। ऐसे निर्णायक मोड़ पर मोहित उल्वा ने अपनी बल्लेबाजी से मैच का पूरा परिदृश्य बदल दिया। उन्होंने परिस्थितियों को समझते हुए पहले पारी को संभाला और फिर जरूरत के अनुसार बड़े शॉट लगाए। मोहित ने केवल 26 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 49 रन बनाए। उनकी पारी में पांच चौके और तीन छक्के शामिल रहे। उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और भारतीय टीम की जीत की उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। खास बात यह रही कि उन्होंने विकेटों के लगातार गिरने के बावजूद अपना संयम नहीं खोया और आखिरी समय तक क्रीज पर टिके रहे।

दूसरे छोर पर चिगुरुपति वेंकट ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आठ गेंदों पर नाबाद 11 रन बनाकर मोहित का साथ दिया। इस साझेदारी ने भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। मुकाबले का रोमांच आखिरी ओवर तक बना रहा। भारतीय टीम को जीत के लिए जरूरी रन जुटाने थे और पाकिस्तान के गेंदबाज हर गेंद पर मैच को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मोहित और वेंकट ने दबाव के बीच सूझबूझ दिखाई और आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने नौ विकेट पर 339 रन बनाते हुए एक विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

पाकिस्तान की ओर से रिजवानुल्लाह ने तीन विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी को झकझोरने की कोशिश की, जबकि निकाब शफीक को दो विकेट मिले। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में लगातार विकेट लेकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया था, लेकिन अंतिम समय में भारतीय बल्लेबाजों के साहस के सामने उनका प्रयास सफल नहीं हो सका। इस जीत के साथ भारतीय युवा टीम ने साबित कर दिया कि बड़े लक्ष्य और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य तथा सामूहिक प्रयास से सफलता हासिल की जा सकती है। फाइनल में कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी, आर्यवीर सहवाग और मनल चौहान की पारियों ने टीम को मजबूत आधार दिया, जबकि निर्णायक क्षणों में मोहित उल्वा और चिगुरुपति वेंकट ने जिम्मेदारी संभालकर जीत की मुहर लगा दी।



जनजातीय गौरव दिवस
सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार
जनजातीय कल्याण योजना



धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की
151वीं जन्म जयंती के अवसर पर
जनजातीय गौरव दिवस का उत्सव

जनजातीय गौरव दिवस
दिनांक : 15 नवंबर 2026



जनजातीय गौरव सप्ताह
दिनांक : 12 से 18 नवंबर 2026



गरिमामय उपस्थिति

श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात
दिनांक : 15 नवंबर 2026 स्थान : छोटाउदेपुर

श्री हर्ष संघवी
माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात
दिनांक : 15 नवंबर 2026 स्थान : वलसाड

"भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान हमारी प्रेरणा है। आदिवासी समाज का सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है और विकसित गुजरात का निर्माण हमारा संकल्प है।"
- हर्ष संघवी, उपमुख्यमंत्री, गुजरात

संपादकीय

चुभती महंगाई

बीते माह देश में खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में उछाल से महंगाई दो साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। यह स्पष्ट है कि देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति महंगाई को काबू में रखने में विफल रही है। चिंता की बात है यह महंगाई दर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित छह फीसदी की तय अधिकतम सीमा को पार कर गई है। इसके साथ ही दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति निर्धारण करने वाली कमेटी की बैठक में नीतिगत ब्याज दर में एक और बढ़ोतरी की आशंका बलवती हुई है। उल्लेखनीय है कि अक्तूबर में भी आरबीआई ने रेपो रेट में 25 आधार अंक का इजाफा किया था। पिछले एक साल से लगातार बढ़ रही खुदरा महंगाई का दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचना बताता है कि लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आई है। जाहिर है इसका दबाव घरेलू बजट पर पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते माह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत तक जा पहुंची है। जिसके चलते अगले माह की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट बढ़ने की संभावना फिर प्रबल हो गई है। आशंका है कि इससे उपभोक्ताओं के घर व वाहन आदि के लोन की मासिक किस्ते लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों, जिनकी मूल्य सूचकांक निर्धारण में चालीस फीसदी की हिस्सेदारी होती है, की महंगाई बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। देश में सब्जियां, दालें और किराना का अन्य सामान महंगा हो गया है। वहीं अनाज, तिलहन और चीनी की कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है। यहां उल्लेखनीय है कि अक्तूबर माह में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई है। यही वजह है कि लोगों को आशंका है कि उनके लिये आने वाली सर्दियों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूं तो महंगाई आजकल, वैश्विक उथल-पुथल और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण विश्वव्यापी समस्या हो गई है। खासकर रूस व यूक्रेन तथा खाड़ी में जारी संघर्ष के चलते पेट्रोलियम पदार्थों व उनसे बनने वाले उत्पादों की आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन भारत में बढ़ती महंगाई के कारणों में मौसम की संवेदनशीलता व मुद्रास्फीति भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि देश में घरेलू महंगाई दर लगातार बारहवें महीने बढ़ी है। खाने-पीने की चीजों के अलावा, इसमें परिवहन से जुड़े खर्च, कपड़े,आवास और भोजन से जुड़ी सेवाओं का भी योगदान रहा है। हालांकि, खाड़ी संघर्ष में स्थितियां सामान्य होने की ओर बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में कुछ गिरावट आई है। यद्यपि, सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को इसका लाभ न मिला हो,लेकिन दामों में कमी अपरोक्ष रूप से कुछ राहत देने वाली जरूर है। इसके बावजूद महंगाई का दबाव बना रहेगा। हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य महंगाई दर अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, जो कमजोर और असमान मानसून के असर को दर्शाती है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि वैश्विक स्तर पर खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ा ही दिया है। निस्संदेह, यह चिंताजनक स्थिति जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर में कुछ उम्मीद भी नजर आ रही है। वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 7.7 रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि आम आदमी के लिये यह स्थिति कष्टकारी हो सकती है। एक आम उपभोक्ता के लिये बढ़ती महंगाई के मायने जरूरी चीजों पर खर्च कम करना हो सकता है। ऐसे में कीमतों को स्थिर रखने की जरूरत और भी बढ़ जाती है। कालाबाजारी करने वालों और कृत्रिम रूप से महंगाई बढ़ाने वाले तत्वों पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। आज की बदलती स्थिति पर नजर रखने और लोगों का बोझ कम करने के लिये आपातकालीन कदम उठाने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही सरकार के लिये भी जरूरी है कि वह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिये प्रशासनिक व मौद्रिक उपायों की दिशा में आगे बढ़े।

क्या नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने लिया बदला? Microsoft Server Down के पीछे साजिश की बात में कितना दम?

> इस तकनीकी संकट की सबसे बड़ी कीमत वैश्विक कारोबार को चुकानी पड़ सकती है। जब कंपनियों के ईमेल बंद हों, ऑनलाइन मीटिंग न हो सके, भुगतान और कारोबारी संचार में रुकावट आए तो नुकसान केवल कुछ घंटों की उत्पादकता का नहीं होता।



Microsoft की सेवाओं में आई तकनीकी गड़बड़ी ने एक बार फिर दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था किस हद तक कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सर्वर और डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर हो चुकी है। ईमेल से लेकर ऑफिस के कामकाज, क्लाउड सेवाओं, ऑनलाइन मीटिंग और कारोबारी संचार तक, जब Microsoft की सेवाएं प्रभावित हुईं तो उसका असर किसी एक देश या कंपनी तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लाखों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर कंपनियों का कामकाज बाधित हुआ और डिजिटल माध्यमों पर निर्भर कारोबार की रफ्तार थम गई।इस व्यवधान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 74 देशों और क्षेत्रों में सेवाओं को लेकर शिकायतें दर्ज हुईं। आउटेज पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर से 74 लाख से अधिक रिपोर्ट दर्ज की गईं। यह वास्तविक प्रभावित यूजर्स की संख्या नहीं है, बल्कि शिकायतों का आंकड़ा है। Microsoft 365 के करोड़ों उपयोगकर्ताओं के लिए Outlook ईमेल सेवा सबसे बड़ी परेशानी बन गई। लोग अपने इनबॉक्स नहीं खोल पा रहे थे, ईमेल भेजने और प्राप्त करने में दिक्कत आ रही थी और कई संदेश घंटों की देरी से पहुंच रहे थे। Teams पर मीटिंग और बातचीत प्रभावित हुई, जबकि Copilot और अन्य क्लाउड आधारित सेवाओं तक पहुंचने में भी समस्याएं आईं।

साथ ही इसका असर केवल दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों तक सीमित नहीं था। अमेरिका में सरकारी संस्थानों और अमेरिकी संसद के कामकाज पर भी असर पड़ा। जापान और सिंगापुर की सरकारी व्यवस्थाओं में दिक्कतें सामने आईं। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी और पुलिस व्यवस्था भी प्रभावित हुई। ब्रिटेन में अस्पतालों, पुलिस और स्वास्थ्य सेवाओं को वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी पड़ी। कई डॉक्टरों और चिकित्सा केंद्रों ने मरीजों से ऑनलाइन संपर्क के बजाय फोन करने को कहा। भारत में IndiGo, Air India और Akasa Air जैसी विमानन कंपनियों की ईमेल सहायता सेवाएं प्रभावित हुईं। ग्राहकों को अपनी शिकायतें और जरूरी सूचनाएं भेजने में परेशानी हुई।

इस तकनीकी संकट की सबसे बड़ी कीमत वैश्विक कारोबार को चुकानी पड़ सकती है। जब कंपनियों के ईमेल बंद हों, ऑनलाइन मीटिंग न हो सके, भुगतान और कारोबारी संचार में रुकावट आए तो नुकसान केवल कुछ घंटों की उत्पादकता का नहीं होता। वित्तीय संस्थानों, शेयर बाजारों, बीमा कंपनियों, शिपिंग और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक इसका असर पहुंचा। रिपोर्टों के मुताबिक, यूरोपीय एक्सचेंज ऑपरेटर Euronext को कंपनियों के साथ संपर्क के लिए फोन का सहारा लेना पड़ा। शिपिंग कंपनी Maersk ने ग्राहकों को जरूरी मामलों में फोन से संपर्क करने को कहा। ब्रिटिश बीमा कंपनी Aviva ने वैकल्पिक फोन नंबरों और दूसरे संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया। ताइवान में एक वित्तीय कंपनी को ट्रेड की पुष्टि के लिए फैक्स तक का सहारा लेना पड़ा। अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी Workhorse Group को अपनी वित्तीय नतीजों से जुड़ी घोषणा टालनी पड़ी।

हालांकि नुकसान का अंतिम वैश्विक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। शुरुआती आकलनों में अरबों डॉलर की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका जताई गई। बीमा क्षेत्र के विश्लेषकों ने इस घटना से जुड़े संभावित बीमित नुकसान का अनुमान 30 से 50 करोड़ डॉलर के बीच लगाया है। वहीं कुछ छोटे कारोबारियों को एक दिन में 30 हजार डॉलर तक का नुकसान होने की खबरें सामने आईं। यानी यह केवल ईमेल सेवा बंद होने का मामला नहीं था, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के कामकाज में पैदा हुई बड़ी रुकावट थी।

Microsoft की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसके सर्वर अचानक अनुपलब्ध होने लगे। इससे बाकी चालू सर्वरों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। कंपनी ने पहले नेटवर्क कॉन्फिगरेशन में बदलाव और सर्वर क्षमता से जुड़ी समस्याओं की बात कही। बाद में 13 नवंबर को कंपनी ने स्पष्ट किया कि समस्या पहले किए गए नेटवर्क क्षमता विस्तार (Network Capacity Upgrade) के दौरान पैदा हुई तकनीकी गड़बड़ी से जुड़ी थी, जो हालिया नेटवर्क बदलाव के बाद सामने आई।

समस्या यह थी कि कुछ सर्वर उपलब्ध नहीं रहे और उनके हिस्से का ट्रैफिक दूसरे सर्वरों पर पहुंचने लगा। इससे दबाव बढ़ा और सुधार के लिए किए गए शुरुआती प्रयास भी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाए। कुछ सर्वर दोबारा चालू किए जाने के बाद फिर से जवाब देने में असफल हो गए। यही वजह रही कि समस्या कुछ घंटों में खत्म होने के बजाय 24 घंटे से ज्यादा खिंच गई। कंपनी को चरणबद्ध तरीके से सेवाएं बहाल करनी पड़ीं।

इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प और गंभीर पहलू सोशल मीडिया पर सामने आया। Microsoft में हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी और पुनर्गठन की खबरें आई थीं। जुलाई में कंपनी ने हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कीं और अक्टूबर में भी कर्मचारियों की संख्या घटाने से जुड़ी खबरें सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में सवाल उठने लगे कि क्या अनुभवी कर्मचारियों की विदाई, लागत घटाने की नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ते भरोसे का इस तकनीकी संकट से कोई संबंध है? क्या नाराज कर्मचारियों ने किसी तरह की जानबूझकर गड़बड़ी की? साथ ही सोशल मीडिया पर साइबर हमले, चीन की कथित भूमिका और अनियंत्रित AI एजेंट से लेकर कर्मचारियों की छंटनी तक को इस घटना से जोड़कर तरह-तरह के दावे किए गए। लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। Microsoft ने स्पष्ट किया कि उसे किसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि या साइबर हमले का संकेत नहीं मिला है। कंपनी ने यह भी कहा कि यह घटना AI या AI एजेंट की वजह से नहीं हुई। छंटनी किए गए कर्मचारियों की किसी साजिश का भी कोई प्रमाण सामने नहीं आया। बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने एक कड़वी हकीकत सामने रख दी है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल Microsoft का एक नेटवर्क संबंधी संकट अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप तक सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, विमानन कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रभावित कर सकता है। जिस डिजिटल व्यवस्था को दुनिया अपनी सबसे बड़ी ताकत मानकर चल रही है, उसी व्यवस्था का एक हिस्सा ठप होते ही करोड़ों लोगों का कामकाज प्रभावित हो गया। Microsoft ने सेवाओं में व्यापक सुधार की जानकारी दी और ग्राहकों से हुई परेशानी के लिए माफी भी मांगी, लेकिन इस घटना से पैदा हुए सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं।

प्रेरणा

सादगी और संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू

भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने अपने पद, प्रतिष्ठा और अधिकार से कहीं अधिक अपने व्यवहार, विचारों और मानवीय संवेदनाओं के कारण लोगों के दिलों में जगह बनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनके व्यक्तित्व में अहंकार का कोई स्थान नहीं था। वे बच्चों से विशेष प्रेम करते थे और उनके साथ समय बिताना उन्हें बेहद पसंद था। उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाएं बताती हैं कि उनके लिए इंसान की पहचान उसका पद नहीं, बल्कि उसका व्यवहार और हृदय की उदारता थी। एक बार की बात है। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तीन मूर्ति भवन के बगीचे में टहल रहे थे। चारों ओर हरियाली थी। पेड़-पौधों के बीच से गुजरती ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को आनंदमय बना रही थी। नेहरू जी प्रकृति से विशेष लगाव रखते थे। उन्हें फूलों, पौधों और बच्चों की दुनिया में एक अलग ही आनंद मिलता था। इसी दौरान अचानक उनके कानों में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उन्हें लगा कि शायद यह उनका भ्रम है, लेकिन जब आवाज दोबारा और अधिक स्पष्ट सुनाई दी तो वे उस दिशा में बढ़ने लगे।

कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटा बच्चा अकेला रोता हुआ दिखाई दिया। नेहरू जी ने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बच्चा लगातार रो रहा था। उन्होंने सोचा कि संभवतः उसकी मां आसपास ही माली के साथ बगीचे में काम कर रही होगी। बच्चे की मासूमियत और उसकी परेशानी देखकर उनका मन द्रवित हो उठा। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता या संकोच के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसे सीने से लगाया और मां की तरह प्यार से थपकियां देने लगे। उनके स्नेह भरे स्पर्श का असर हुआ और कुछ ही क्षणों में बच्चा रोना बंद कर मुस्कराने लगा।

कुछ समय बाद बच्चे की मां वहां पहुंची। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे। वह काम में व्यस्त होने के कारण कुछ देर के लिए बच्चे से दूर हो गई थी। जैसे ही उसने बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी। वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं उसके बच्चे को गोद में लेकर उसे दुलार रहे हैं। बच्चा भी उनकी गोद में प्रसन्न होकर पेड़-पौधों की ओर देख रहा था। मां की आंखों में सम्मान और कृतज्ञता के भाव उमड़ आए। उसके लिए यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। देश का सर्वोच्च राजनीतिक पद संभालने वाला व्यक्ति एक सामान्य परिवार के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे चुप करा रहा था। नेहरू जी ने इस घटना के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्ची महानता पद और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता में होती है।

दरअसल, बच्चों के प्रति नेहरू जी का प्रेम केवल भावनात्मक लगाव तक सीमित नहीं था। वे बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। उनका विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आने वाली पीढ़ी में छिपी होती है। यदि बच्चों को अच्छा वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वतंत्र विचार और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलें तो वे देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। वे बच्चों की जिज्ञासाओं को महत्व देते थे और चाहते थे कि उनमें सवाल पूछने, नई चीजें सीखने तथा अपने आसपास की दुनिया को समझने की आदत विकसित हो।

नेहरू जी का मानना था कि बच्चों के मन में भय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास होना चाहिए। उन्हें अनुशासन के साथ स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी प्रतिभा और कल्पनाशक्ति का विकास कर सकें। वे बच्चों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करते, उनकी बातें ध्यान से सुनते और उनकी मासूम जिज्ञासाओं का उत्तर देने का प्रयास करते थे। यही कारण था कि बच्चे भी उनसे सहज रूप से जुड़ जाते थे। उनके व्यक्तित्व में एक ओर देश के प्रधानमंत्री की गंभीरता थी तो दूसरी ओर बच्चों के साथ बच्चा बन जाने वाली सरलता भी थी। बच्चों के प्रति उनके इसी विशेष प्रेम और लगाव के कारण उनके जन्मदिन 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन केवल एक महान नेता को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी अवसर है। विद्यालयों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चे गीत, नृत्य, नाटक और खेलकूद के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। शिक्षक भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करते हैं।

नेहरू जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों और मानवीय मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी बच्चे के आंसू पोंछना और किसी अनजान व्यक्ति के प्रति अपनापन दिखाना ही सच्चे संस्कारों की पहचान है। जीवन में सफलता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सफलता के साथ विनम्रता और संवेदनशीलता बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज जब समाज में प्रतिस्पर्धा, स्वार्थ और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है, तब नेहरू जी के जीवन से जुड़ी ऐसी घटनाएं हमें मानवीयता का महत्व समझाती हैं। उनका संदेश स्पष्ट है कि बच्चों को केवल अच्छे अंक प्राप्त करने या भविष्य में बड़ा पद हासिल करने की शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना भी उतना ही जरूरी है। उनके भीतर प्रेम, करुणा, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सादगी और बच्चों के प्रति उनका स्नेह आज भी प्रेरणा देता है। तीन मूर्ति भवन के बगीचे में एक अनजान बच्चे को गोद में उठाने की घटना हमें याद दिलाती है कि महानता का वास्तविक परिचय बड़े-बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे मानवीय कार्यों से मिलता है। यही कारण है कि नेहरू जी केवल देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू के रूप में भी लोगों के हृदय में सदैव जीवित रहेंगे।

अभियान

संतान की खुशहाली के लिए पूजी जाती हैं छठी मइया, षष्ठी देवी से जुड़ी है महापर्व की मान्यता

भारतीय धार्मिक परंपराओं में कुछ पर्व ऐसे हैं, जिनका संबंध केवल देवी-देवताओं की उपासना से नहीं, बल्कि परिवार, संतान और प्रकृति के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारियों से भी जुड़ा हुआ है। छठ महापर्व ऐसा ही एक अनुपम पर्व है। इसमें सूर्य देव की आराधना के साथ छठी मइया की पूजा का विशेष विधान है। लोकमान्यता है कि छठी मइया बच्चों की संरक्षिका हैं। उनकी कृपा से संतान को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि माताएं अपने बच्चों के कल्याण और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से यह कठिन व्रत रखती हैं। छठ पूजा में दिखाई देने वाला त्याग, तपस्या और विश्वास इस पर्व को अन्य धार्मिक आयोजनों से विशिष्ट बनाता है।

छठ महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पूजा के लिए किसी भव्य मंदिर या विशेष धार्मिक स्थल की अनिवार्यता नहीं होती। नदी, तालाब, पोखर अथवा किसी स्वच्छ जलाशय के किनारे श्रद्धालु एकत्रित होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मिट्टी, जल, फल, फूल और सूर्य की किरणों के माध्यम से प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। इसी पूजा के बीच छठी मइया का स्मरण किया जाता है। लोकविश्वास के अनुसार वे संतान के जीवन की रक्षा करती हैं और परिवार पर अपना स्नेह बनाए रखती हैं। इस पर्व में महिलाएं केवल अपनी संतान के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवार के मंगल और समाज की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करती हैं।

धार्मिक ग्रंथों और लोकपरंपराओं में छठी मइया का संबंध षष्ठी देवी से जोड़ा जाता है। उन्हें प्रकृति की छठी शक्ति का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि षष्ठी देवी बच्चों के जन्म, पालन-पोषण और संरक्षण से संबंधित शक्ति हैं। वे निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान करने वाली तथा बच्चों को संकटों से बचाने वाली देवी के रूप में पूजी जाती हैं। कुछ लोकपरंपराओं में उन्हें सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है। इसी विश्वास के कारण छठ पर्व में सूर्य की उपासना के साथ छठी मइया की आराधना की जाती है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्पत्ति और स्वरूप से जुड़ी कथाओं में अंतर मिलता है, लेकिन सभी मान्यताओं का केंद्र संतान का कल्याण और परिवार की मंगलकामना है।

षष्ठी देवी की महिमा से जुड़ी एक प्रचलित पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी रानी मालिनी की है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत के राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उनका जीवन सुख-सुविधाओं और राजसी वैभव से परिपूर्ण था, लेकिन संतान न होने के कारण वे और उनकी रानी हमेशा दुखी रहते थे। वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा करने के बाद भी जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो दोनों ने ऋषि-मुनियों से मार्गदर्शन लेने का निर्णय किया।

एक दिन राजा ने महर्षि कश्यप के समक्ष अपनी व्यथा रखी। उन्होंने बताया कि संतान के अभाव में उनका जीवन अधूरा महसूस होता है। महर्षि ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। राजा ने पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ यज्ञ संपन्न कराया। कुछ समय बाद रानी मालिनी गर्भवती हुईं और निर्धारित समय पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन यह खुशी अधिक देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि नवजात शिशु मृत पैदा हुआ था।

राजा और रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिली संतान को इस अवस्था में देखकर वे व्याकुल हो उठे। राजा प्रियव्रत का धैर्य जवाब दे गया। वे अपने पुत्र के वियोग में इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का विचार कर लिया। तभी एक दिव्य शक्ति वहां प्रकट हुई। देवी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उन्होंने राजा को बताया कि वे षष्ठी देवी हैं और संसार में बच्चों की रक्षा तथा संतान सुख प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं।

देवी ने राजा को निराश न होने का संदेश दिया और अपनी आराधना करने के लिए कहा। उन्होंने संतान सुख का आशीर्वाद भी दिया। राजा प्रियव्रत ने देवी के निर्देशानुसार श्रद्धापूर्वक उनका पूजन किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवी की कृपा से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। तभी से षष्ठी देवी की पूजा की परंपरा का विस्तार हुआ। बाद में यह आराधना लोकजीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। विशेष रूप से बच्चों के जन्म, उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए षष्ठी देवी का पूजन किया जाने लगा।

इसी परंपरा से जुड़ी एक अन्य मान्यता बच्चे के जन्म के छठे दिन होने वाले छठियार संस्कार की है। अनेक परिवारों में नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन विशेष पूजा आयोजित की जाती है। इस दिन षष्ठी देवी का स्मरण कर बच्चे की सुरक्षा और अच्छे भविष्य की कामना की जाती है। ग्रामीण और पारंपरिक समाज में इस अवसर का विशेष महत्व है। घर की महिलाएं मंगलगीत गाती हैं और देवी से बच्चे को स्वस्थ, दीर्घायु तथा संस्कारी बनाने का आशीर्वाद मांगती हैं। इस परंपरा में मां की ममता और नवजात के प्रति परिवार के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है।

छठ महापर्व में छठी मइया की पूजा का मुख्य उद्देश्य संतान की रक्षा, परिवार का कल्याण और जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति है। व्रती महिलाएं कठिन नियमों का पालन करते हुए भगवान सूर्य और छठी मइया के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करती हैं। वे अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छी शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और सफल जीवन की कामना करती हैं। जिन परिवारों में संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, वहां भी छठी मइया के प्रति विशेष आस्था देखने को मिलती है। लोगों का विश्वास है कि माता की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में खुशहाली आती है। इस महापर्व में सूर्य देव की उपासना का भी गहरा धार्मिक और प्राकृतिक महत्व है। सूर्य को पृथ्वी पर जीवन का आधार माना जाता है। उनकी किरणों से पेड़-पौधों को ऊर्जा मिलती है, मौसम का संतुलन बना रहता है और अच्छे भविष्य जीव-जगत को जीवन मिलता है। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि उनकी उपस्थिति और महत्ता को मनुष्य प्रतिदिन अनुभव करता है। छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालु जीवन के प्रत्येक चरण के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं।

छठ पूजा की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इस दिन व्रती स्नान कर घर की साफ-सफाई करते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना का विधान होता है। व्रती पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ की खीर, रोटी और अन्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद निर्जला व्रत शुरू होता है, जो लगभग 36 घंटे तक चलता है। तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन किया जाता है। इन चार दिनों के दौरान घरों में भक्ति, पवित्रता और अनुशासन का विशेष वातावरण बना रहता है। छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की अपनी अलग पहचान है। ठेकुआ, कसार, नारियल, केला, गन्ना, सिंघाड़ा और मौसमी फलों का विशेष महत्व है। बांस की टोकरी और सूप में सजाकर प्रसाद को घाट तक ले जाया जाता है। प्रसाद तैयार करने में शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कई परिवारों में इसे पारंपरिक तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। इन सामग्रियों में स्थानीय कृषि और प्राकृतिक उपज की झलक मिलती है।

ऐसे ही चलता रहा तो Bangladesh को America और China के हाथों बेच देंगे Tarique Rahman!

क्या बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार अपने देश को चीन और अमेरिका के हाथों बेच रही है या गिरवी रख रही है? यह सवाल हम नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोग उठा रहे हैं। दरअसल, बांग्लादेश में एक तरफ चीन की सरकारी कंपनी को महंगी LNG परियोजना का ठेका देकर देश की ऊर्जा व्यवस्था को लंबे समय के लिए विदेशी कंपनी के हवाले करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते की शर्तों को लेकर भी विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। बांग्लादेश में असंतोष इस बात को लेकर है कि आखिर सरकार बिना अपने राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों का आकलन किए, विदेशी शक्तियों के सामने हर शर्त पर हामी क्यों भर रही है? सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक समझौतों और बड़े-बड़े निवेश के नाम पर बांग्लादेश को चीन और अमेरिका की रणनीतिक गिरफ्त में धकेला जा रहा है?हम आपको बता दें कि ताजा विवाद की शुरुआत कॉक्स बाजार के महेशखाली इलाके में प्रस्तावित तीसरे फ्लोटिंग LNG टर्मिनल से हुई है। 12 नवंबर 2026 को बांग्लादेश सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी China National Energy Engineering and Construction Company (CNEE) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए 15 वर्षों में लगभग 12,324 करोड़ टका और 20 वर्षों में करीब 13,161 करोड़ टका भुगतान का प्रस्ताव है।

विवाद की सबसे बड़ी वजह इसकी लागत है। कंपनी ने प्रतिदिन 3.42 लाख डॉलर की रीगैसीफिकेशन फीस प्रस्तावित की है, जो मौजूदा अमेरिकी कंपनी Excelerate Energy की फीस से लगभग 35 प्रतिशत और Summit LNG की फीस से करीब 37 प्रतिशत ज्यादा है। यानी जिस सेवा के लिए पहले से कम भुगतान किया जा रहा है, उसी सेवा के लिए अब चीन की कंपनी को काफी अधिक रकम देने का सवाल खड़ा हो गया है। यह प्रस्ताव अक्टूबर में लागत की समीक्षा के लिए वापस लिया गया था, लेकिन नवंबर में इसे फिर मंजूरी मिल गई। ऐसे में बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर महंगी शर्तों के बावजूद इस समझौते को आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?

बांग्लादेश में इस फैसले को लेकर ऊर्जा विशेषज्ञों और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े लोगों की आपत्तियां सामने आई हैं। बांग्लादेश की Consumers Association से जुड़े ऊर्जा सलाहकार एम. शमसुल आलम ने सवाल उठाया है कि जब अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते प्रस्ताव मौजूद थे, तब महंगी पेशकश को आगे बढ़ाने का आधार क्या था? देखा जाये तो यह केवल एक कारोबारी सौदा नहीं है। LNG जैसी बुनियादी ऊर्जा व्यवस्था में किसी विदेशी कंपनी के साथ 15 से 20 साल का समझौता देश को लंबे समय तक एक खास तकनीकी और आर्थिक व्यवस्था से बांध सकता है। साथ ही बांग्लादेश की परेशानी केवल चीन तक सीमित नहीं है। अमेरिका के साथ फरवरी 2026 में हुआ व्यापार समझौता भी देश के भीतर भारी राजनीतिक विवाद का विषय बन चुका है। इस समझौते के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन हुए हैं। वामपंथी संगठनों, नागरिक अधिकार समूहों और अर्थशास्त्रियों ने इसे असमान समझौता बताते हुए रद्द करने की मांग की है। आलोचकों की आपत्ति है कि समझौते में बांग्लादेश के लिए 131 शर्तें हैं, जबकि अमेरिका पर केवल छह शर्तों की बाध्यता है। इसके अलावा डिजिटल व्यापार, ऊर्जा, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता मिलने की आशंका जताई गई है। समझौते के प्रावधानों को लेकर यह सवाल भी उठा है कि अगर बांग्लादेश किसी तीसरे देश के साथ ऐसा डिजिटल व्यापार समझौता करता है जिसे अमेरिका अपने हितों के खिलाफ मानता है, तो वाशिंगटन समझौता समाप्त करके ऊंचे टैरिफ फिर लागू कर सकता है। इसके अलावा, अमेरिकी LNG की खरीद और अमेरिकी उत्पादों के आयात को लेकर भी विरोध है। प्रदर्शनक

हसीना की वापसी पर भारत की दो शर्तें, सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी जरूरी

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। इस बीच बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने हसीना की बांग्लादेश वापसी के लिए दो अहम शर्तें रखी हैं। भारत चाहता है कि उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाए और बांग्लादेश में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि उन्हें सुनवाई के बाद मौत की सजा दी जाती है तो उनके पास उसके खिलाफ अपील करने का पर्याप्त कानूनी अवसर हो। हालांकि, भारत सरकार की ओर से इन कथित शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की चिंता केवल प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हसीना की वापसी के बाद उनके साथ होने वाले व्यवहार और कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर भी है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में उनके मामले की सुनवाई पारदर्शी तरीके से हो और उस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय तथा मीडिया की नजर बनी रहे। इस तरह दोनों देशों के बीच बातचीत में प्रत्यर्पण की कानूनी औपचारिकताओं के साथ मानवाधिकार, सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पहलू भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हसीना को भारत से बांग्लादेश ले जाने के लिए दो संभावित विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प यह है कि बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस लाने के लिए अपना सैन्य विमान भेजे। दूसरा विकल्प भारत-बांग्लादेश सीमा पर उन्हें बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों को सौंपने का हो सकता है। हालांकि, इन विकल्पों पर अंतिम सहमति बनने या किसी आधिकारिक व्यवस्था की घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है। इससे संकेत मिलता है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को लेकर अभी कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श बाकी है।

शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए व्यापक छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। उनके सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया। नई राजनीतिक व्यवस्था के दौरान उनके खिलाफ कई कानूनी मामले सामने आए और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में भी मुकदमा चला। हसीना की भारत में



मौजूदगी के बाद से ही बांग्लादेश की ओर से उनकी वापसी की मांग उठती रही है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा और संवेदनशील हो गया। बांग्लादेश ने भारत से उन्हें वापस सौंपने की मांग की। दूसरी ओर, भारत के सामने यह सवाल है कि प्रत्यर्पण की स्थिति में हसीना की सुरक्षा और उनके साथ होने वाली कानूनी कार्रवाई को लेकर क्या आश्वासन उपलब्ध होगा। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट में जिन दो शर्तों का उल्लेख किया गया है, वे इसी चिंता से जुड़ी बताई गई हैं।

सजा और अपील की प्रक्रिया बनी अहम मुद्दा

हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी वापसी का मामला सामान्य प्रत्यर्पण विवाद से आगे बढ़ गया है। किसी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपने के फैसले में कानूनी प्रक्रिया, सुरक्षा और उसके अधिकारों से जुड़े सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि हसीना को बांग्लादेश लौटने के बाद निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले। यदि उनके खिलाफ मौत की सजा का फैसला बरकरार रहता है तो उन्हें उसके खिलाफ अपील करने का अधिकार भी सुनिश्चित किया जाए।

भारत की कथित दूसरी शर्त इसी पहलू से जुड़ी है। इसके अलावा भारत यह भी चाहता है कि मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मीडिया की नजर रहे। इससे सुनवाई की पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों पर ध्यान बना रह सकेगा। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये शर्तें बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट में किए गए दावे हैं और भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से इनकी पुष्टि नहीं की है।

दिसंबर में वापसी की चर्चा से बढ़ी कूटनीतिक हलचल

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में कुछ हद तक सहमति बनने के बाद शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कही है। यदि ऐसा होता है तो यह बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। हालांकि, उनकी वापसी की तारीख, यात्रा के तरीके और प्रत्यर्पण की औपचारिक प्रक्रिया को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

बांग्लादेश के सैन्य विमान भेजने का विकल्प सामने आने से यह भी संकेत मिलता है कि वापसी की व्यवस्था को लेकर सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा विकल्प सीमा पर बांग्लादेशी सेना को सौंपने का है। दोनों विकल्पों में सुरक्षा और आधिकारिक समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऐसे किसी भी कदम के लिए दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों के बीच सहमति और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक होगा।

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में शेख हसीना का मामला पहले से ही संवेदनशील विषय बना हुआ है। हसीना लंबे समय तक बांग्लादेश की राजनीति में प्रभावशाली नेता रही हैं और उनके कार्यकाल में भारत के साथ दोनों देशों के संबंधों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। सत्ता परिवर्तन के बाद उनके भारत में रहने और बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण की मांग ने द्विपक्षीय संबंधों के सामने नई चुनौती खड़ी की है।

फिलहाल भारत सरकार की ओर से कथित दो शर्तों या प्रत्यर्पण के संभावित तरीकों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट में किए गए दावों को अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत और आधिकारिक बयानों से ही स्पष्ट होगा कि शेख हसीना की वापसी को लेकर क्या सहमति बनती है और उनकी सुरक्षा तथा निष्पक्ष सुनवाई के मुद्दे पर किस तरह की व्यवस्था तय की जाती है।

12 जनवरी से वडोदरा-जामनगर इंटरसिटी ट्रेन के नंबर परिवर्तित

ट्रेन परिचालन व रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के मद्देनजर कई ट्रेनें के सुपरफास्ट से एक्सप्रेस में परिवर्तित होने के चलते ट्रेन नंबरों में बदलाव किया गया है। इसी के चलते 12.01.2027 से पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल के अंतर्गत ट्रेन न. 22959/22960 वडोदरा- जामनगर वडोदरा सुपरफास्ट के नम्बरों में बदलाव कर 19029/19030 वडोदरा - जामनगर वडोदरा एक्सप्रेस किया गया है, साथ ही दोनों दिशाओं की ट्रेनों के किराये में होगी कमी होगी।

इसके अलावा वडोदरा-जामनगर इंटरसिटी के जामनगर आगमन समय में 10 मिनट का बदलाव किया गया। दूसरी ओर जामनगर-वडोदरा इंटरसिटी के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री खेमराज मीना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा-जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नया ट्रेन नंबर 19029 होगा। अब यह ट्रेन अपने वर्तमान के निर्धारित समय 23:30 बजे के



स्थान पर 23:40 बजे जामनगर पहुंचेगी। वहीं ट्रेन नंबर 22960 जामनगर-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस का नया ट्रेन नंबर 19030 होगा। इस ट्रेन के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा की योजना बनाते समय संशोधित ट्रेन नंबर एवं समय का ध्यान रखें। यात्री विस्तृत जानकारी एवं अद्यतन समय-सारणी के लिए रेलवे की अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in देख सकते हैं।

पंजाब में तीर्थयात्रियों से भरी दो बसों की भीषण भिड़ंत, चार की मौत

तरनतारन। पंजाब के तरनतारन जिले में शनिवार को तीर्थयात्रियों से भरी दो बसों के बीच हुई भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि डेढ़ दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों में 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा जम्मू-कश्मीर-राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौशहरा पन्नूआं के पास हुआ। दोनों बसें फिरोजपुर से अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए जा रही थीं। रास्ते में अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में आगे चल रही बस के चालक ने ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रही दूसरी बस उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कई लोग घायल होकर बसों में ही फंस गए।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सड़क सुरक्षा फोर्स की टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को बसों से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए



पहुंचीं तीन एंबुलेंस भी यातायात जाम में फंस गईं, जिससे राहत कार्य के दौरान अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों बसें फिरोजपुर से अमृतसर की ओर जा रही थीं। यात्रियों का उद्देश्य श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचकर मत्था टेकना था। इसी दौरान नौशहरा पन्नूआं के नजदीक सड़क पर एक बाइक सवार सामने आ गया। उसे बचाने के लिए आगे चल रही बस के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे आ रही दूसरी बस का चालक समय रहते वाहन पर नियंत्रण नहीं कर पाया और बस आगे चल रही बस से जा भिड़ी। अचानक हुई इस टक्कर से दोनों वाहनों में बैठे यात्रियों को जोरदार झटका लगा। कई यात्री सीटों से उछलकर गिर पड़े, जबकि कुछ को चोटें आईं।

टक्कर के बाद दोनों बसों में सवार लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई। आसपास मौजूद लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस के आने से पहले घायलों की सहायता में जुट गए। सड़क सुरक्षा फोर्स और पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। बसों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने और उन्हें प्राथमिक सहायता दिलाने का काम किया गया। इसके बाद घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 10 यात्रियों को विशेष चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए भी प्रयास किए। दुर्घटनाग्रस्त बसों के कारण सड़क पर वाहनों की कतारें लग गईं। एंबुलेंस को अस्पताल पहुंचने में भी परेशानी हुई। तीन एंबुलेंस के ट्रैफिक जाम में फंसने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में पुलिस और राहत दल ने रास्ता खुलवाने तथा घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम किया।

तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र लांबा के मुताबिक, पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दुर्घटना में चार यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि डेढ़ दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें 10 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

इस दुर्घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अचानक ब्रेक लगाने और पीछे चल रहे वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने की जरूरत को रेखांकित किया है। खासकर तीर्थयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बसों से लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में वाहन चालकों की सतर्कता, निर्धारित गति सीमा का पालन और सड़क पर अचानक सामने आने वाली परिस्थितियों से निपटने की तैयारी बेहद जरूरी है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है और घायलों का उपचार जारी है।

16 नवंबर को प्रतापनगर - रक्सौल के बीच वन वे स्पेशल ट्रेन सेवा

यात्रियों की सुविधा व मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल के प्रतापनगर से रक्सौल स्टेशन के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेन की एक ट्रिप चलायी जा रही है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन नंबर 09133 प्रतापनगर - रक्सौल वन- वे स्पेशल प्रतापनगर से 16 नवंबर 2026 (सोमवार) को रात 23:50 बजे प्रस्थान करेगी और बुधवार की सुबह 06:30 बजे रक्सौल पहुंचेगी।

यह ट्रेन वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा और नरकटियागंज स्टेशनों पर ठहरेंगी। इस ट्रेन में स्लीपर व द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 09133 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी



की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर मंडल में आयोजित दो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविरों में 120 से अधिक रेलवे पेंशनरों ने लिया लाभ

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में रेलवे पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से 13 नवंबर 2026 को रेलवे कम्युनिटी हॉल, भावनगर परा में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) शिविर का आयोजन किया गया।

रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भावनगर मंडल में 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान-5 चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मंडल के सात स्टेशनों पर विशेष DLC शिविर आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत पहला शिविर बोटाद रेलवे स्टेशन पर सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है, जबकि 13 नवंबर को भावनगर परा में दूसरा शिविर आयोजित किया गया। दोनों शिविरों में अभी तक



120 से अधिक रेलवे पेंशनरों ने लाभ लिया है।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन ने उपस्थित पेंशनरों को रेलवे प्रशासन द्वारा उनके हित में उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल तकनीक के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया।

कार्यक्रम में सहायक मंडल वित्त प्रबंधक श्री संजय सक्सेना एवं पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। पेंशनरों एवं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रेलवे प्रशासन द्वारा उनकी सुविधा एवं कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत आगामी विशेष DLC शिविर 17 नवंबर को जूनागढ़, 18 नवंबर को जेतलसर, 19 नवंबर को वेरावल, 24 नवंबर को पोरबंदर तथा 25 नवंबर को महुवा रेलवे स्टेशन पर आयोजित किए जाएंगे।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर पेंशनर भावनगर परा स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के लेखा विभाग अथवा अपने क्षेत्र के वेलफेयर इंस्पेक्टर से संपर्क कर सकते हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी रेलवे पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों से अपील की है कि वे इस डिजिटल सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाएं तथा अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित समय-सीमा में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराएं।

मंडल वित्त प्रबंधक श्री हरिश जनसारी ने कहा कि शिविर में आने वाले पेंशनर अपने साथ आधार कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश (PPO), बैंक पासबुक (खाता संख्या एवं IFSC विवरण सहित) तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर अवश्य लाएं।

भावनगर मंडल रेल प्रशासन पेंशनरों के कल्याण, उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान तथा उन्हें सरल, सुलभ एवं डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान इसी प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

गाजा के बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के लिए रास्ता खोले इजराइल : ईयू

ब्रसेल्स। गाजा में भारी बारिश और बाढ़ से पैदा हुए संकट के बीच यूरोपीय संघ (ईयू) ने इजराइल से प्रभावित लोगों तक तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने की मांग की है। ईयू ने कहा है कि राहत संगठनों को गाजा में बिना किसी बाधा के प्रवेश दिया जाना चाहिए, ताकि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। संघ ने सभी सीमा चौकियों को फिर से खोलने और राहत सामग्री की आपूर्ति लगातार जारी रखने पर भी जोर दिया है।

यूरोपीय संघ ने अपने बयान में कहा कि गाजा में मौजूदा हालात को देखते हुए मानवीय सहायता और शुरुआती पुनर्वास से जुड़ी सामग्री बड़े पैमाने पर पहुंचाने की तत्काल जरूरत है। इसके लिए इजराइल को राहत संगठनों को निर्बाध रास्ता उपलब्ध कराना चाहिए। ईयू के अनुसार, सभी सीमा मार्गों को फिर से खोलना जरूरी है, ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंच सके और राहत कार्यों में किसी तरह की



रुकावट न आए।

गाजा में भारी बारिश के कारण पहले से कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बाढ़ के चलते राहत और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत अधिक हो गई है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय राहत संगठनों के सामने प्रभावित आबादी तक सहायता पहुंचाने की चुनौती है। ईयू ने इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत सामग्री के प्रवेश और वितरण में तेजी लाने की आवश्यकता जताई है।

इससे पहले पिछले सप्ताह इजराइली सैन्य निकाय सीओजीएटी (कोऑर्डिनेटर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द टेरिटरीज) ने कहा था कि उसने भारी बारिश शुरू होने से पहले गाजा में स्वच्छता की स्थिति सुधारने के प्रयास तेज किए थे। इस काम के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय किया गया था। सीओजीएटी के अनुसार, बारिश से पैदा होने वाली संभावित समस्याओं को देखते हुए संबंधित व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी।

दूसरी ओर, गाजा में राहत सामग्री के प्रवेश को लेकर इजराइल और आलोचकों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी जारी हैं। इजराइल ने सीओजीएटी पर पर्याप्त राहत सामग्री गाजा में प्रवेश नहीं देने के आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि इस तरह के आरोप हमास की जिम्मेदारी से ध्यान भटकाने का प्रयास हैं। इजराइल ने अपनी ओर से राहत सामग्री की आपूर्ति को लेकर उठाए गए सवालों पर असहमति जताई है।

ऐसे में गाजा में बाढ़ प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने का मुद्दा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में है। यूरोपीय संघ ने सीमा मार्ग खोलने और राहत संगठनों को बिना बाधा काम करने देने की मांग दोहराई है। आने वाले समय में राहत सामग्री की उपलब्धता और उसके वितरण की व्यवस्था से ही प्रभावित लोगों को तत्काल मदद मिलने की स्थिति स्पष्ट होगी।

अक्टूबर में भारत का वस्तु निर्यात 45.06 प्रतिशत बढ़ा; शीर्ष 50 बाजारों में से 43 में वृद्धि से वैश्विक पहुंच के विस्तार का संकेत: फियो

नई दिल्ली : अक्टूबर 2026 में भारत का वस्तु निर्यात 45.06 प्रतिशत बढ़कर 49.47 बिलियन डॉलर हो गया। देश के शीर्ष 50 निर्यात गंतव्यों में से 43 में शिपमेंट का विस्तार हुआ है, जो मजबूत गति और व्यापक बाजार लाभ को दर्शाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वस्तु और सेवाओं को मिलाकर कुल निर्यात 89.99 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जो 29.90 प्रतिशत की वृद्धि है।

इस प्रदर्शन का स्वागत करते हुए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष श्री एस. सी. रल्हन ने कहा: "अक्टूबर का प्रदर्शन विकास की गति और इसके भौगोलिक विस्तार, दोनों ही दृष्टि से उत्साहजनक है। हमारे शीर्ष 50 बाजारों में से 43 में विस्तार, भारतीय निर्यातकों की मजबूती और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बावजूद अवसरों का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। अब प्राथमिकता इस मजबूत गति को निरंतर निर्यात वृद्धि में बदलने की है।"

वस्तु निर्यात अक्टूबर 2025 में 34.11 बिलियन डॉलर और सितंबर 2026 में 44.40 बिलियन डॉलर था। इस वृद्धि में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, कपड़ा और परिधान, चावल, तथा प्लास्टिक और लिनोलियम का योगदान रहा। अमेरिका को निर्यात में 39 प्रतिशत, चीन को 48 प्रतिशत और जापान को 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि ब्रिटेन, ताइवान और केन्या को भेजे जाने वाले शिपमेंट में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्पेन में 352 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मलेशिया, टोगो, सिंगापुर और मिस्र को होने वाला निर्यात दोगुने से भी अधिक हो गया। पश्चिम एशिया को भेजे जाने वाले शिपमेंट में भी सकारात्मक रुझान रहा, जिसमें 3.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

श्री रल्हन ने कहा, "स्थापित और उभरते बाजारों में हुई बढ़त, बाजार विविधीकरण के महत्व को दर्शाती है। निर्यातकों को खरीदारों के साथ मजबूत संबंध बनाकर, प्रतिस्पर्धी उत्पादों की पेशकश करके और भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली सुविधाओं का बेहतर लाभ उठाकर इन अवसरों का पूरा फायदा उठाना चाहिए।"

अप्रैल-अक्टूबर 2026-27 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात लगभग 568.84 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के 487.59 बिलियन डॉलर के मुकाबले 16.66 प्रतिशत की वृद्धि है। फियो अध्यक्ष ने कहा, "पहले सात महीनों में लगातार हुई वृद्धि, भारत की निर्यात क्षमताओं में विश्वास को मजबूत करती है। यह 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक उत्साहजनक गति प्रदान करती है। इस गति को बनाए रखने के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना आवश्यक होगा।" फियो ने बताया कि अक्टूबर में वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त व्यापार घाटा घटकर 20.09 बिलियन डॉलर रह गया, जो एक साल पहले 25.15 बिलियन डॉलर था। हालांकि, वस्तुओं का व्यापार घाटा बढ़कर 39.88 बिलियन डॉलर हो गया, जिसका कारण वस्तुओं का अधिक आयात होना है।

श्री रल्हन ने जोर देकर कहा कि निर्यात के लिए किफायती ऋण, कम लेनदेन लागत और कुशल लॉजिस्टिक्स इस गति को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, खासकर एमएसएमई निर्यातकों के लिए। उन्होंने कहा, "सरकार और उद्योग के बीच निरंतर सहयोग, समय पर मिलने वाली सहायता और व्यापार समझौतों का प्रभावी उपयोग, अक्टूबर के इस शानदार प्रदर्शन को वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में स्थायी लाभ में बदलने में मदद कर सकता है।"

मिशन 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, 21 नवंबर को लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुटी है। इसी राजनीतिक सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को लखनऊ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में देशभर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। आधिकारिक रूप से यह कार्यक्रम कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से करीब एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री का लखनऊ दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है। यही वजह है कि पार्टी चुनाव की औपचारिक घोषणा से काफी पहले संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को भी इसी व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में देखा जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों के जरिए युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पहुंच मजबूत की जाए।

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी चुनाव की रणनीति और जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद से संगठन ने बूथ स्तर पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर भी पार्टी विशेष ध्यान दे रही है। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में पार्टी की निगरानी और भागीदारी बनी रहे।



पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित होगा कौशल दीक्षांत समारोह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर का कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में देशभर के आईटीआई के करीब 1,500 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें लगभग 1,000 विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से और करीब 200 विद्यार्थी दूसरे राज्यों से आएंगे। कार्यक्रम में 40 ट्रेड और छह जोन के लगभग 64 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें उत्तर प्रदेश के छह विद्यार्थी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री विभिन्न ट्रेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे।

इस आयोजन की खास बात यह है कि कौशल दीक्षांत समारोह पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है। अब तक इसका आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में होता रहा है। इस बार लखनऊ को आयोजन स्थल बनाया गया है। प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू हुए इस कार्यक्रम के राजधानी में आयोजन को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश के कौशल विकास संस्थानों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों के साथ शामिल होंगे। कौशल विकास के क्षेत्र में आईटीआई की भूमिका, रोजगारपरक प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को तैयार करने जैसे विषय भी इस आयोजन के केंद्र में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़े हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम प्रदेश के युवाओं के बीच भी विशेष संदेश देने वाला माना जा रहा है।

मोदी और शाह की सक्रियता से बढ़ेगी चुनावी हलचल

उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति केवल बड़े कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। पार्टी आने वाले समय में संगठन और जनसंपर्क के स्तर पर अपनी गतिविधियों को और व्यापक बनाने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े क्षेत्रीय कार्यक्रमों और जनसभाओं के माध्यम से चुनावी माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संगठनात्मक मजबूती और चुनावी प्रबंधन पर विशेष ध्यान देंगे।

अमित शाह के प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों का दौरा करने की तैयारी भी की जा रही है। इन दौरों के दौरान क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिला स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर संगठन की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। बूथ प्रबंधन, सामाजिक समीकरण, मतदाता संपर्क और सरकार की योजनाओं के प्रचार जैसे मुद्दे भी इन बैठकों के केंद्र में रह सकते हैं। हालांकि इन गतिविधियों का विस्तृत कार्यक्रम सामने आना अभी बाकी है, लेकिन पार्टी के भीतर चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रियता बढ़ने के संकेत स्पष्ट हैं।

भाजपा की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठन के हर स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर दी जाएं। प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व यह भी चाहता है कि सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। इसके लिए जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

एसआईआर और बूथ प्रबंधन पर भी पार्टी का जोर

आगामी चुनाव की तैयारियों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण भी भाजपा के एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पार्टी संगठन इस अभियान को लेकर बूथ स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, संशोधन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। संगठन की नजर इस बात पर भी है कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम सक्रिय रहे और स्थानीय स्तर पर मतदाताओं से संपर्क बना रहे।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बूथ प्रबंधन और स्थानीय संगठन की भूमिका निर्णायक होती है। यही कारण है कि भाजपा चुनाव से पहले अपने संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करने में जुटी है। केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता के साथ प्रदेश संगठन को भी चुनावी मोड में लाने की कोशिश की जा रही है।

सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की तैयारियां

प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए शासन और प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्था, अतिथियों के आगमन, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। कार्यक्रम दोपहर बाद प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

कुल मिलाकर 21 नवंबर का लखनऊ दौरा कौशल विकास और युवाओं के सम्मान से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित होगा, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता भाजपा की चुनावी तैयारियों को नई गति दे सकती है। आने वाले दिनों में संगठनात्मक बैठकों, क्षेत्रीय दौरों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए पार्टी अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

छठ के रंग में रंगी राजधानी, 1400 से अधिक घाटों पर तैयारियां पूरी

नई दिल्ली। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ राजधानी दिल्ली में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शहर के अलग-अलग इलाकों में छठ गीतों की गूंज सुनाई दे रही है और घाटों पर व्रतियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी में 1400 से अधिक छठ घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षा, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पर्व के अवसर पर विभिन्न घाटों पर पहुंचकर छठ व्रतियों के साथ सूर्य उपासना में शामिल होंगी। वह रविवार, 15 नवंबर को सोनिया विहार छठ घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी, जबकि सोमवार, 16 नवंबर की सुबह आईटीओ स्थित हाथी घाट पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी।

छठ महापर्व को लेकर दिल्ली के पूर्वांचली बहुल इलाकों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। घाटों को सजाया गया है और श्रद्धालुओं की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्रती या श्रद्धालु को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। घाटों पर साफ-सफाई और स्वच्छ पानी की उपलब्धता के साथ रोशनी, सुरक्षा, शौचालय तथा महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बड़े छठ घाटों पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी,



ताकि किसी समस्या की स्थिति में तत्काल समाधान किया जा सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छठ पूजा के दौरान व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा गया है। प्रशासनिक स्तर पर अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे पर्व के दौरान समन्वय के साथ काम किया जा सके। सरकार का प्रयास है कि व्रती निर्बाध रूप से पूजा कर सकें और परिवारों के साथ घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित तथा सुविधाजनक माहौल मिले।

इस बार उत्तरी दिल्ली में मुनक नहर के किनारे करीब 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट भी विकसित किया गया है। इसे छठ पर्व की तैयारियों का प्रमुख हिस्सा माना जा रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में पूजा की व्यवस्था के लिए साफ-सफाई, प्रकाश और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे-बड़े घाटों को भी पूजा के लिए तैयार किया गया है, ताकि लोगों को अपने घरों के आसपास ही अर्घ्य देने की सुविधा मिल सके।

मुख्यमंत्री ने छठ महापर्व को लोकपरंपरा, सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व बताया है। छठ पूजा में सूर्य और जल की उपासना के माध्यम से प्रकृति के प्रति सम्मान तथा परिवार और समाज के कल्याण की कामना की जाती है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए पूजा-अर्चना करते हैं। खरना के बाद निर्जला व्रत शुरू होता है और व्रती नदी, तालाब या निर्धारित घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी तथा उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं।

इसी क्रम में राजधानी में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी छठ के आयोजन किए जा रहे हैं। दिल्ली भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा के नेतृत्व में पंचशील एनक्लेव में खरना पूजा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी शामिल हुए। नेताओं ने खरना पूजा में भाग लिया और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया।

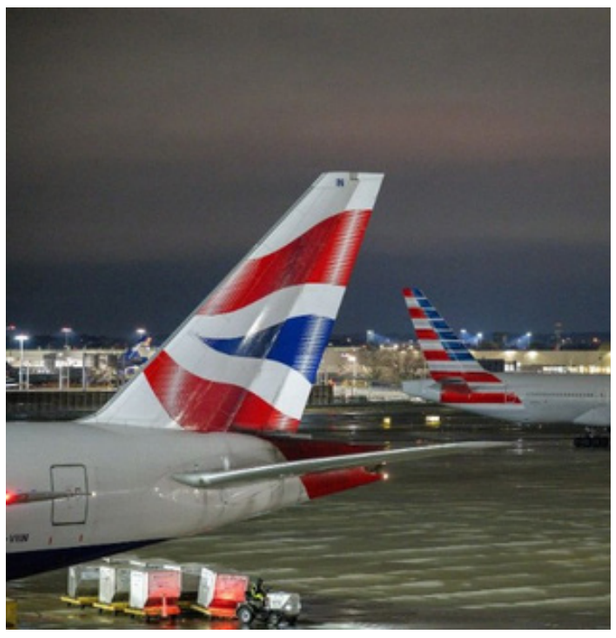
कार्यक्रम में छठ महापर्व की परंपरा और सामाजिक एकता के महत्व को रेखांकित किया गया। छठ पूजा पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा प्रमुख पर्व है, लेकिन अब यह दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। राजधानी में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, इसलिए छठ के दौरान दिल्ली के अनेक इलाकों में गांव-जैसा उत्सवी माहौल दिखाई देता है। पूजा समितियां, स्थानीय निवासी और सामाजिक संगठन मिलकर घाटों की व्यवस्था तथा प्रसाद वितरण जैसे कार्यों में योगदान देते हैं।

रविवार शाम व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान के कल्याण की कामना करेंगे। इसके बाद सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर छठ महापर्व का समापन होगा। दिल्ली सरकार ने दोनों दिनों के लिए घाटों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। राजधानी में 1400 से अधिक घाटों पर की गई तैयारियों के बीच अब श्रद्धालु पूरी आस्था और उत्साह के साथ सूर्य उपासना की तैयारी में जुटे हैं।

अमेरिका में हवाई यातायात बहाल, उड़ानों का परिचालन पटरी पर लौटने में लगेगा समय

वाशिंगटन। अमेरिका में कई घंटे तक वाणिज्यिक हवाई यातायात बाधित रहने के बाद उड़ानों का संचालन फिर से शुरू हो गया है, लेकिन हवाई सेवाओं को पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। करीब 12 घंटे तक चले ग्राउंड स्टॉप के कारण हजारों यात्रियों को हवाई अड्डों पर परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवहन मंत्री सीन डफी ने यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि हवाई यात्रा सुरक्षित है, हालांकि उन्होंने आगाह किया कि परिचालन व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के दौरान उड़ानों में देरी और उनके रद्द होने की स्थिति बनी रह सकती है।

परिवहन मंत्री डफी के अनुसार, हवाई यातायात बहाल होने का मतलब यह नहीं है कि सभी उड़ानें तत्काल अपने निर्धारित समय पर संचालित होने लगेंगी। ग्राउंड स्टॉप के दौरान विमानों की आवाजाही रुकने से एयरलाइंस का पूरा परिचालन कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। कई विमान अपने निर्धारित स्थानों पर नहीं पहुंच सके, जबकि चालक दल की तैनाती भी प्रभावित हुई। अब एयरलाइंस को विमानों और कर्मचारियों



को अलग-अलग हवाई अड्डों पर फिर से व्यवस्थित करना होगा। इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है।

डफी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर यात्रियों से अपील की कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से उड़ान की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर लें। उन्होंने कहा कि यात्रियों को उड़ानों के समय में बदलाव, संभावित देरी और रद्द होने की सूचना के लिए एयरलाइंस के संपर्क में रहना चाहिए।

करीब 12 घंटे तक लागू रहे ग्राउंड स्टॉप के कारण हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंस गए थे। कई यात्रियों को अपनी यात्रा टालनी पड़ी, जबकि कुछ को लंबा इंतजार करना पड़ा। उड़ानों के परिचालन में आई इस बाधा का असर केवल तत्काल उड़ानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विमानों के आगे के निर्धारित कार्यक्रम और चालक दल की उपलब्धता पर भी पड़ा।

परिवहन विभाग की ओर से हवाई यातायात सुरक्षित होने का भरोसा दिए जाने के बावजूद यात्रियों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एयरलाइंस के परिचालन कार्यक्रम को सामान्य बनाने के लिए विमानों और चालक दल की पुनर्तैनाती की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में भी कुछ उड़ानों के समय में बदलाव या उन्हें रद्द किए जाने की स्थिति बन सकती है। यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे अपनी उड़ान से जुड़ी जानकारी लगातार जांचते रहें।

कुलगाम हमले के पीछे लश्कर मॉड्यूल का शक, तीन ओजीडब्ल्यू जांच के घेरे में

श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के नाके पर हुए आतंकी हमले की जांच तेज कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के एक मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। जांच का दायरा स्थानीय आतंकी अब्दुल लतीफ और दो पाकिस्तानी आतंकियों तक पहुंच गया है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हमले को अंजाम देने से पहले आतंकियों ने किस तरह इलाके की रेकी की और उन्हें स्थानीय स्तर पर किसका सहयोग मिला। तीन संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) भी जांच के घेरे में हैं। अब तक 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि 20 संदिग्धों को आगे की जांच के लिए हिरासत में रखा गया है।

सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले नाके और उसके आसपास के इलाके की गतिविधियों पर नजर रखी थी। इसके लिए स्थानीय मददगारों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा रहा है। जांचकर्ता यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमले के बाद आतंकियों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने में किसी स्थानीय नेटवर्क ने सहायता की थी या नहीं। हालांकि, लश्कर मॉड्यूल और संदिग्ध ओजीडब्ल्यू की भूमिका को लेकर अभी जांच जारी है और किसी की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

घटना 11 नवंबर को दोपहर करीब 2:15 बजे अखरान इलाके में मीर बाजार के पास हुई थी। यहां सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के नाके को आतंकियों ने निशाना बनाया। प्रत्यक्ष हमले में एके राइफलों से की गई ताबड़तोड़ गोलीबारी के दौरान तीन जवान घायल हो गए थे। घायलों की पहचान हेड कांस्टेबल सोमवीर सिंह, कांस्टेबल राकेश दास



और कांस्टेबल संतोष चंदू के रूप में हुई थी। सोमवीर सिंह के हाथ और राकेश दास के पैर में गोली लगी थी, जबकि संतोष चंदू के पेट और रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। तीनों जवानों को तत्काल सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अनंतनाग ले जाया गया था। बाद में संतोष चंदू की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए श्रीनगर स्थित 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, हमले को बेहद कम समय में अंजाम दिया गया। शुरुआती जानकारी में आतंकियों के मोटरसाइकिल से आने की आशंका जताई गई थी, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद जांच की दिशा में बदलाव आया। फुटेज और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर एजेंसियां अब आतंकियों के आने-जाने के संभावित रास्तों और उनकी गतिविधियों की कड़ियां जोड़ रही हैं। जांच से जुड़े इनपुट के अनुसार, आतंकियों ने दलदली जमीन और पेड़ों से घिरे इलाके का फायदा उठाया। उन्होंने नाके से करीब 50 मीटर की दूरी से गोलीबारी की। रिपोर्ट के मुताबिक, एके राइफलों से लगभग 15 सेकंड के भीतर करीब 30 राउंड गोलियां चलाई गईं। इसके बाद हमलावर घने पेड़ों और दुर्गम रास्तों का सहारा लेकर मौके से फरार हो गए। सुरक्षा एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि हमलावरों ने भागने के लिए पहले से कोई रास्ता तय किया था या फिर उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों का फायदा उठाकर अचानक दिशा बदली।

घटनास्थल से बरामद खाली कारतूस भी जांच का महत्वपूर्ण आधार बने हुए हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ इन कारतूसों की जांच कर रहे हैं, ताकि हथियारों और इस्तेमाल किए गए गोला-बारूद के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। एजेंसियां यह भी मिलान कर रही हैं कि क्या इन कारतूसों का संबंध दक्षिण कश्मीर में पहले हुई आतंकी घटनाओं से हो सकता है। यदि किसी पुराने मामले में इस्तेमाल किए गए हथियार या कारतूसों से समानता मिलती है तो इससे हमले के पीछे सक्रिय आतंकी नेटवर्क की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

जांच के दौरान पिछले दो दिनों में 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। इनमें स्थानीय निवासी और ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी गतिविधियों या संपर्कों को लेकर एजेंसियों को जानकारी मिली थी। पूछताछ के बाद ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन कम से कम 20 संदिग्धों को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। इनमें तीन ऐसे लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिन पर लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर होने का शक है। हालांकि, अभी तक किसी की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ओजीडब्ल्यू को आतंकी संगठनों का स्थानीय मददगार माना जाता है।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ऐसे लोग आतंकियों को ठहरने की जगह उपलब्ध कराने, इलाके की जानकारी देने, सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखने और रसद या अन्य सहायता पहुंचाने में भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से जांच में संदिग्ध ओजीडब्ल्यू के संपर्कों, फोन रिकॉर्ड और आवाजाही से जुड़ी जानकारियों की पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अलग-अलग स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही हैं। जांच का मकसद केवल गोलीबारी करने वाले आतंकियों तक पहुंचना नहीं, बल्कि उनके पीछे सक्रिय पूरे मददगार नेटवर्क का पता लगाना है। एजेंसियां यह जानना चाहती हैं कि हमले से पहले रेकी किसने की, आतंकियों को पनाह किसने दी और वारदात के बाद उनके फरार होने में किसने सहायता की।

स्थानीय आतंकी अब्दुल लतीफ और दो पाकिस्तानी आतंकियों की संभावित भूमिका की जांच भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सुरक्षा एजेंसियां उनके संपर्कों और क्षेत्र में सक्रिय नेटवर्क के बारे में सूचनाएं जुटा रही हैं। फिलहाल जांच सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्यों, पूछताछ और संदिग्धों के संपर्कों के आधार पर आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में इन साक्ष्यों के विश्लेषण से हमले में शामिल आतंकियों और उनके स्थानीय मददगारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने एक दिन में होने वाला सर्वोच्च राजस्व और फ्रेट आय का बनाया रिकॉर्ड



पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष में एक दिन में सर्वोच्च 12.98 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले मंडल ने एक दिन में 11.37 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था। इसके अंतर्गत पैसेंजर, फ्रेट राजस्व, पार्सल व टिकट चेकिंग चेकिंग रेवेन्यू की मुख्य भूमिका रही।

दूसरी ओर मंडल ने हाल में ही एक दिन 10.81 करोड़ का फ्रेट से राजस्व अर्जित कर चालू वर्ष का अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड भी बनाया है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार इसके पहले मंडल ने एक दिन में 9.32 करोड़ की माल ढुलाई आय दर्ज की थी। इसमें कोयला, अनाज, स्टील कॉइल्स, पाइप व कंटेनर जैसी प्रमुख सामग्रियों महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस तरह मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के नेतृत्व में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए, यात्री सुविधाओं और माल परिवहन में वडोदरा मंडल ने नया मानक तय किया है।

पश्चिम रेलवे आठ वन-वे स्पेशल ट्रेनें चलाएगी

त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे 15 और 16 नवंबर, 2026 को बांद्रा टर्मिनस, वलसाड, उधना प्रतापनगर और अहमदाबाद से आठ वन-वे स्पेशल ट्रेनें चलाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रत्येक ट्रेन एक दिशा में एक फेरा लगाएगी।

1. ट्रेन संख्या 09113 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर स्पेशल 15 नवंबर, 2026 को 04:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 19:30 बजे गोरखपुर पहुँचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना, ईदगाह आगरा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग जंक्शन, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर ठहरेगी।

2. ट्रेन संख्या 09063 वलसाड–राजगीर स्पेशल 15 नवंबर, 2026 को 08:45 बजे वलसाड से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 22:30 बजे राजगीर पहुँचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन नवसारी, भेस्तान, चलथान, बारडोली, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना जंक्शन, पटना साहिब, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ और नालंदा स्टेशनों पर ठहरेगी।



3. ट्रेन संख्या 09067 वलसाड–समस्तीपुर स्पेशल 15 नवंबर, 2026 को 22:20 बजे वलसाड से प्रस्थान करेगी तथा 17 नवंबर, 2026 को 10:00 बजे समस्तीपुर पहुँचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन नवसारी, भेस्तान, चलथान, बारडोली, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

4. ट्रेन संख्या 09081 उधना–गया स्पेशल 15 नवंबर, 2026 को 19:45 बजे उधना से प्रस्थान करेगी तथा 17 नवंबर, 2026 को 00:45 बजे गया पहुँचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन चलथान, बारडोली, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, डेहरी ऑन सोन और इस्माइलपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

5. ट्रेन संख्या 09089 उधना–बरौनी स्पेशल 15 नवंबर, 2026 को 21:45 बजे उधना से प्रस्थान करेगी तथा 17 नवंबर, 2026 को 07:30 बजे बरौनी पहुँचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन चलथान, बारडोली, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

6. ट्रेन संख्या 09061 उधना–झंझारपुर स्पेशल 16 नवंबर, 2026 को 21:45 बजे उधना से प्रस्थान करेगी तथा 18 नवंबर, 2026 को 10:00 बजे झंझारपुर पहुँचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन चलथान, बारडोली, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और सकरी स्टेशनों पर ठहरेगी।

7. ट्रेन संख्या 09133 प्रतापनगर–रक्सौल स्पेशल 16 नवंबर, 2026 को 23:50 बजे प्रतापनगर से प्रस्थान करेगी तथा 18 नवंबर, 2026 को 06:30 बजे रक्सौल पहुँचेगी। मार्ग में यह ट्रेन वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

8. ट्रेन संख्या 09431 अहमदाबाद–मधुबनी स्पेशल 15 नवंबर, 2026 को 10:10 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान करेगी तथा 17 नवंबर, 2026 को 01:40 बजे मधुबनी पहुँचेगी। मार्ग में यह ट्रेन आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, उज्जैन, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, दमोह, कटनी मुड़वारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और सकरी स्टेशनों पर ठहरेगी।

उपर्युक्त सभी ट्रेनों में शयनयान श्रेणी और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच होंगे। उपर्युक्त सभी ट्रेनों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर खुली है। ये सभी स्पेशल ट्रेनें विशेष किराये पर चलेंगी। इन ट्रेनों के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर ठहराव के समय की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।